

Title: Regarding reported scam in the disposal of assets of the Kanpur units of National Textile Corporation.

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : अध्यक्ष जी, एनटीसी, यूपी की बंदी हेतु प्रस्तावित मिल इकाइयों की सम्पत्ति की बिक्री हेतु बीआईएफआर द्वारा Asset Sale Committee को दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार टेंडर नोटिसों को तीन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर, उसमें आरक्षित मूल्य न दर्शाते हुए, मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित कर, सम्पत्ति का उच्चतम मूल्य देने वाले निविदा दाता को सम्पत्ति की बिक्री की जानी थी। परन्तु न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर की 16 एकड़ भूमि पर बनी बिल्डिंग को गिराकर उसका मलवा बिना कोई टेंडर नोटिस प्रकाशित कराए ही, एक ठेकेदार को मात्र एक करोड़ तीन लाख पचास हजार रुपये में बेच दिया गया। केवल इतना ही नहीं, नियमों की अवहेलना करते हुए सार्वजनिक उपक्रम की सम्पत्ति को बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाये एक ही पार्टी से वार्ता कर आरक्षित मूल्य एक करोड़ तीन लाख पचास हजार रुपये पर ही क्यों बेचा गया? एनटीसी की जो भी सम्पत्ति टेंडर प्रक्रिया द्वारा बेची गयी, उसका मूल्य आरक्षित धनराशि से दोगुना से भी अधिक प्राप्त हुआ है। केवल इतना ही नहीं, एनटीसी यूपी की लार्ड कृणा टेक्सटाइल्स मिल्स के प्रबंधक वित्त को एनटीसी होल्डिंग कंपनी के सतर्कता विभाग द्वारा कराई गयी जांच में पचास लाख रुपये से भी अधिक धनराशि के घोटाले के लिए जिम्मेदार पाया गया था। इस पर एनटीसी होल्डिंग कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री एस.के. चतुर्वेदी, आई.ए.एस, एनटीसी यूपी के चेयरमैन ने श्री के.आर. पिल्लई को पत्र संख्या डी.ओ. नं. 5(1) 2003-बीआईजी (774) दिनांक 11-11-2003 प्रेषित कर उस प्रबंधक (वित्त) को दोगी पाए जाने पर तुरंत निलम्बित कर कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की। परन्तु मंत्रालय के दबाव में एनटीसी यूपी के चेयरमैन द्वारा दोगी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण उसे साक्ष्य मिटाने का अवसर मिल रहा है। एनटीसी यूपी की बंद की जा रही मिल इकाइयों में नियुक्त एनटीसी के शो रह गये 87 कर्मचारियों, अधिकारियों को जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत अपने त्याग पत्र नहीं दिए हैं, ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को एनटीसी की अन्य इकाइयों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों में कब तक समायोजित कर दिया जाएगा, जैसा कि एक अन्य सार्वजनिक उपक्रम (बीआईसी) में कार्यरत ऐसे ही कर्मचारियों को पहले ही समायोजित किया जा चुका है। सर, यह बहुत महत्वपूर्ण इश्यु है, इस पर कपड़ा मंत्रालय से जवाब आना चाहिए।

श्री ई.अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष जी, ₹(व्यवधान)मैंने इस कंपनी के बारे में पाइंट रेज किया था₹(व्यवधान)मुझे कोई जवाब नहीं मिला है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष जी, मुझे भी बोलना है।

अध्यक्ष महोदय : बिहार को छोड़कर दूसरा कोई इश्यु हो तो आप बोल सकते हैं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामचन्द्र पासवान।